"आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतवासियों के लिए आज एक मंत्र बन गया है"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियां

दिसंबर 2020

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

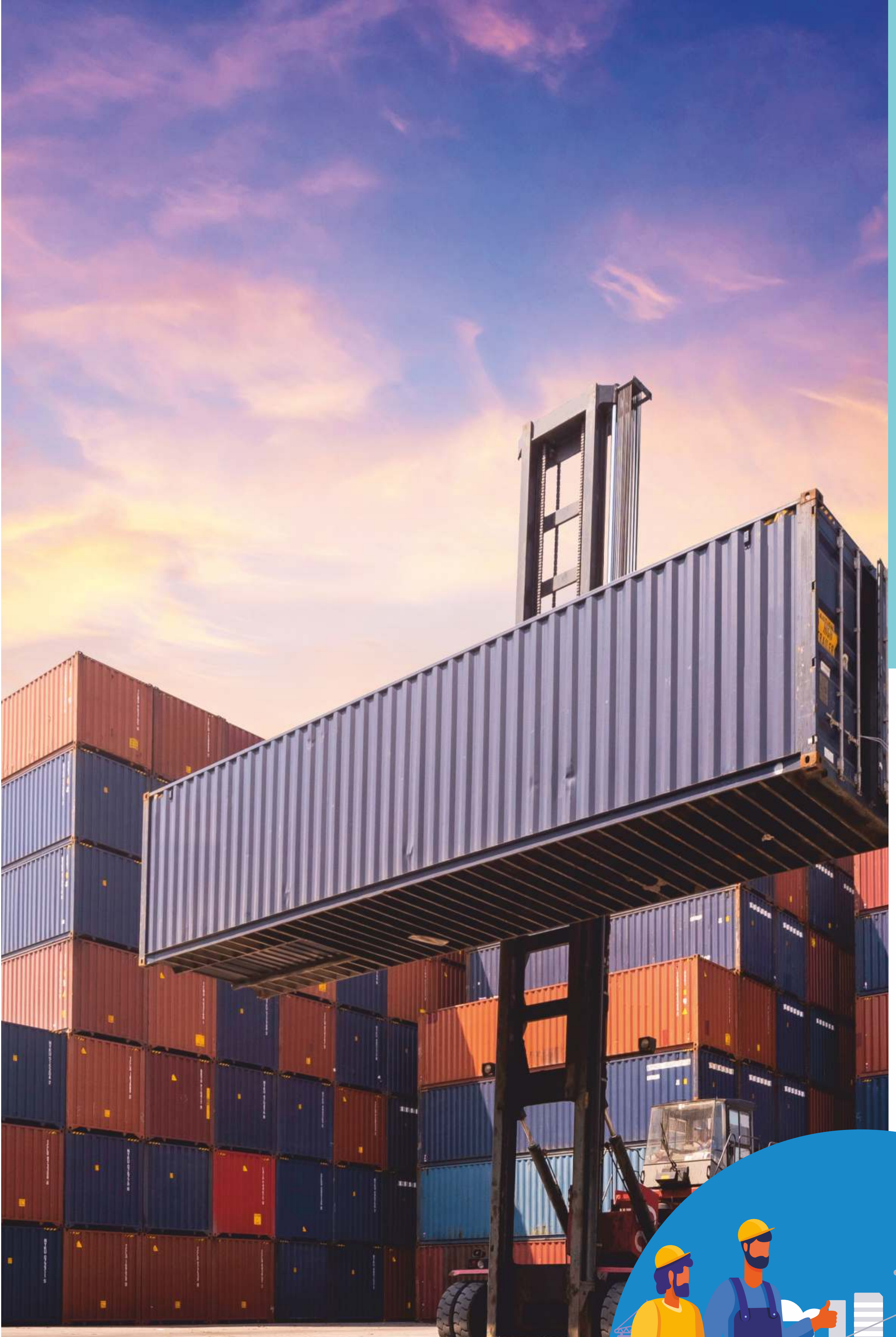

कोविड-19 के दौरान निर्यातकों एवं एमएसएमई को राहत

- **विदेश व्यापार नीति** को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया
- **एडवांस ऑथोराइज़ेशन देने की वैधता** को 6 माह के लिए बढ़ाया गया

- **निर्यात लाइसेंस संबंधी आवेदन** करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को संशोधित किया गया
- प्याज, काजू और पाम ऑयल जैसी मूल्य संवेदनशील सामग्रियों के **आयात और निर्यात को विनियमित** करने के लिए समय पर उपाय
- **कोविड-19 हेल्पडेस्क**

- **एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड** को 6 माह के लिए बढ़ाया गया
- **3 लाख करोड़ रुपये** के प्रावधान वाली आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (इसीएलजीएस) एमएसएमई के लिये 100% क्रेडिट गारंटी और कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक ऋण है
- एमएसएमई में इक्विटी इन्फ्यूज़न के लिए फंड ऑफ फंड्स और रियायती ऋण के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त सहायता
- रेहड़ी-पटरी वालों के लिए क्रेडिट सुविधा (पीएम स्वनिधि योजना)

आत्मनिर्भर भारत : आपदा को अवसर में बदलना

57,600 वेंटीलेटर का निर्माण केवल तीन महीनो में किया, जबकि कोविड से पहले घरेलु स्तर पर लगभग कोई वेंटीलेटर नहीं बनता था

4 गुना बढ़ोत्तरी हुई सैनिटाइज़र उत्पादन में, 200 डिस्टिलरी और 1,000 निर्माताओं द्वारा

5 लाख पीपीई प्रतिदिन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता

नये भारत की ताकत, आत्मनिर्भर भारत

वसुधैव कुटुम्बकम : मानवता की सेवा

मानवीय आधार पर **120 देशों** को दवाइयों पर छूट दी गई

'मेक-इन-इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए पीपीई मेडिकल कवर ऑल, सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मे और सैनिटाइज़र के निर्यात की अनुमति दी

MAKE IN INDIA

लोकल से ग्लोबल की ओर

भारत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए 24 प्राथमिकता वाले क्षेत्र

विशेषज्ञों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से चिन्हित किए गए

घरेलू क्षमताओं पर निर्माण करना

सुगमता और नीतिगत समाधानों के माध्यम से वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाने एवं रोजगार सृजन करने के लिए

$526 बिलियन 2019-20 में कुल निर्यात (सेवा और वस्तुएं), आधा ट्रिलियन से अधिक

$3.6 बिलियन बिलियन मूल्य के मसालों का निर्यात 2019-20 में अब तक के उच्चतम स्तर पर

100 आदिवासी उत्पादों की प्रोत्साहन के लिए पहचान की गई

500 जिलों के लिए निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई

घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर क्षेत्र

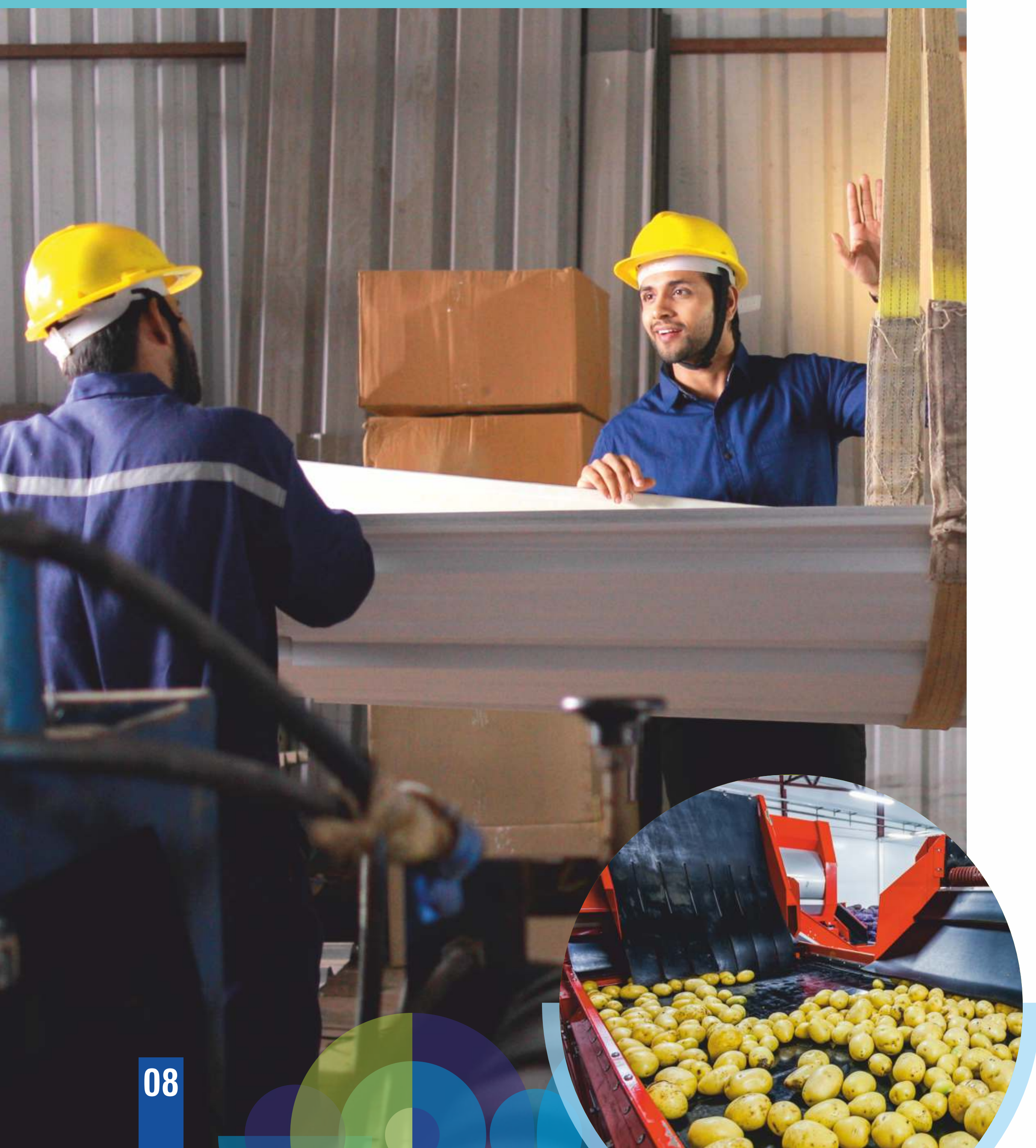

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम और नियमों में संशोधन किए गए

लगभग **$47 बिलियन** के फोकस प्रोडक्ट्स के आयात के लिए **टेक्निकल रेगुलेशंस (टीआर)** - यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम गुणवत्ता वाले और हानिकारक उत्पाद बाजार में प्रवेश न करें

173 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई और **44 वस्तुएं** निषेध/प्रतिबंधित की गई

शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार : एंटी डंपिंग जांच आरंभ करने के लिए औसत समय को कम करके 33 दिन किया गया

आवेदन करने हेतु घरेलू उद्योग, विशेषकर **एमएसएमई**, की सहायता के लिए हेल्पडेस्क

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को बढ़ावा

बजटीय सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित **औद्योगिक इकाइयों को 2,130 करोड़ रुपये वितरित किए गए**

हिमालयी राज्यों के लिए **विशेष पैकेज योजना के तहत ₹578** करोड़ रुपये का वितरण किया गया

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए **नई औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस)** को दिनांक 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया

भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग नक़्शे पर

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य 4 औद्योगिक क्षेत्रों में पूरा होने वाला है, धोलेरा औद्योगिक सिटी, गुजरात; शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र; एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश; आईआईटी विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश

सभी प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट पर **लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक परियोजना** को सफलतापूर्वक लागू किया गया

मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य उद्योगों को लगाने हेतु निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जीआईएस युक्त **लैंड बैंक** पोर्टल का शुभारम्भ

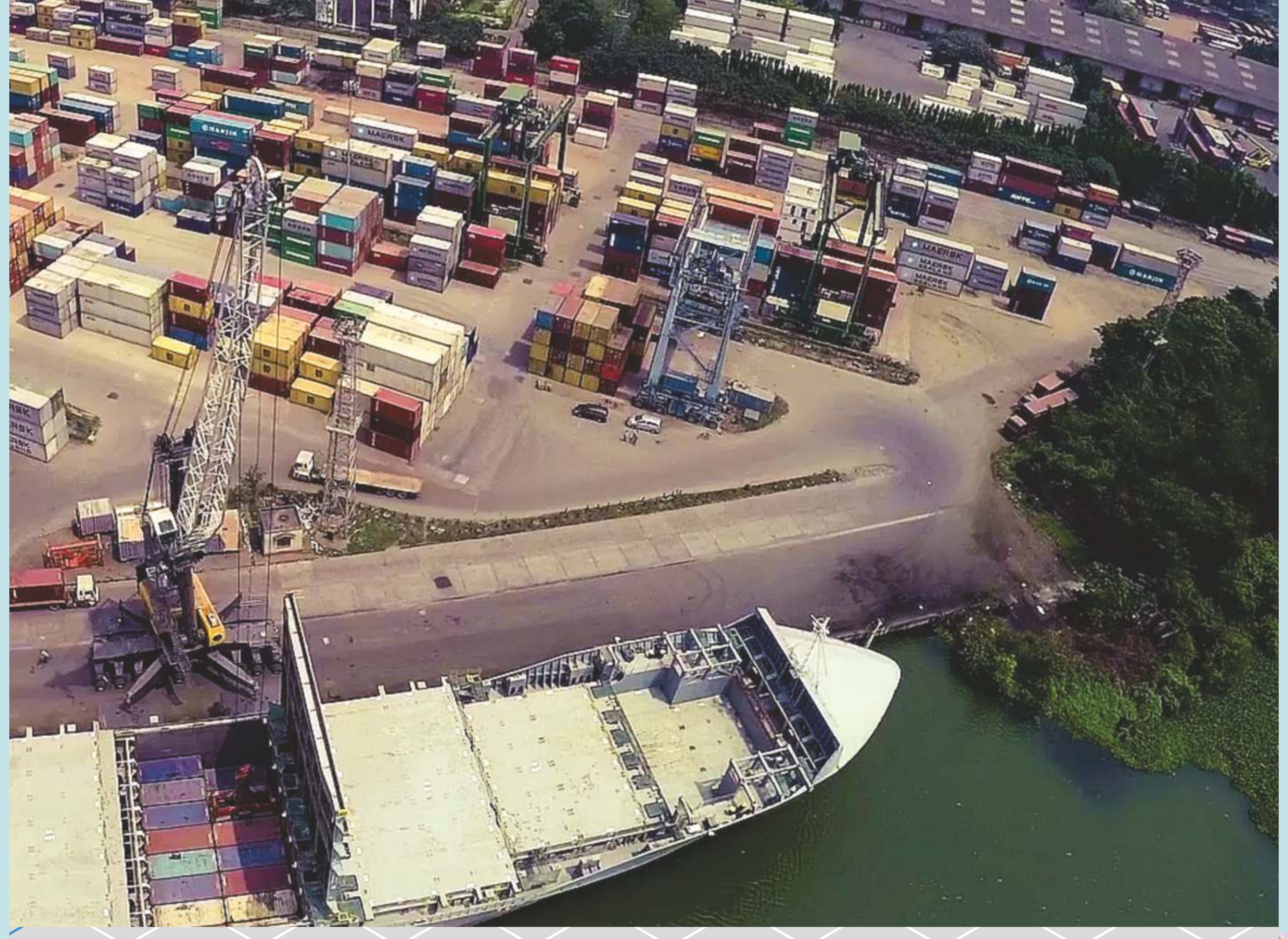

व्यापारिक वार्ता क्षेत्र में भारत अग्रणी

भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में सफलतापूर्वक अपना पक्ष रखा

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा में अच्छी प्रगति

निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय निर्यात पर लगाई गई विभिन्न **नॉन टैरिफ अवरोध** से संबंधित नियमित हस्तक्षेप

भारत ने एफटीए की समीक्षा के लिए आसियान में पहले ही अनुबंध कर लिया है – यह भारतीय निर्यात और मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा देने में सहायता करेगा

एफडीआई इनफ्लो में वृद्धि

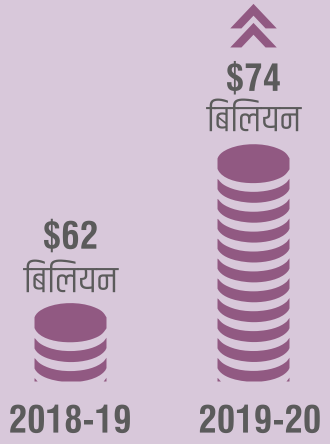

एफडीआई में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2020-21 में, कोविड -19 के बावजूद, अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान **$ 39.9 बिलियन** एफडीआई के साथ एफडीआई में **11%** की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान एफडीआई $ 36.1 बिलियन था।

कोयला खनन गतिविधियों और अनुबंध विनिर्माण में **100 प्रतिशत** एफडीआई की अनुमति

स्थानीय सोर्सिंग द्वारा **सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग (एसबीआरटी)** में सुलभ और लचीला संचालन

अवसरवादी नियंत्रण/अधिग्रहण से भारतीय कंपनियों की सुरक्षा के लिए **एफडीआई नीति में संशोधन** किया गया

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में शीर्ष 10 सुधारकर्ताओं में

भारत ने 10 में से **7 संकेतकों में अपनी रैंक में सुधार** किया है

भारत लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 सुधारकर्ताओं में से एक है और 3 वर्षों में **67 स्थान** का सुधार किया

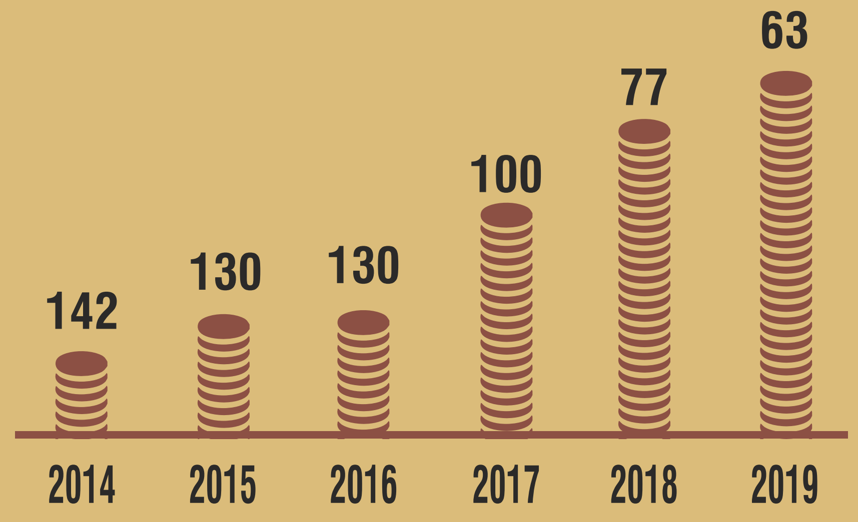

वर्ष 2019 के लिए बिजिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की घोषणा की गई

यह प्रत्येक राज्य में निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होगा

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के माध्यम से पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया

तीसरे पक्ष का निरीक्षण सरकारी निरीक्षणों के अनुरूप

इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल की स्थापना की दिशा में कार्यरत

व्यवसाय संचालन आरंभ करने के लिए आवश्यक सभी केंद्रीय और राज्य मंजूरी प्राप्त करने हेतु वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म

~ 930 फार्म और मंजूरी की पहचान की गई

सरकारी खरीद में मेक-इन-इंडिया को बढ़ावा

₹200 करोड़ से कम की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडरिंग की आवश्यकता नहीं

50 प्रतिशत से अधिक की स्थानीय सामग्री के साथ स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता

भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक स्थितियों के कारण **40,000 करोड़** रुपये से अधिक की निविदाएं रद्द/संशोधित की गई

जीईएम के साथ प्रोक्योरमेंट को नया रूप

जीईएम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस)
- छोटे व्यवसाय और एमएसएमई के लिए वरदान

एक पारदर्शी, कुशल और तेज पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रणाली

ई-कॉमर्स में समान अवसर

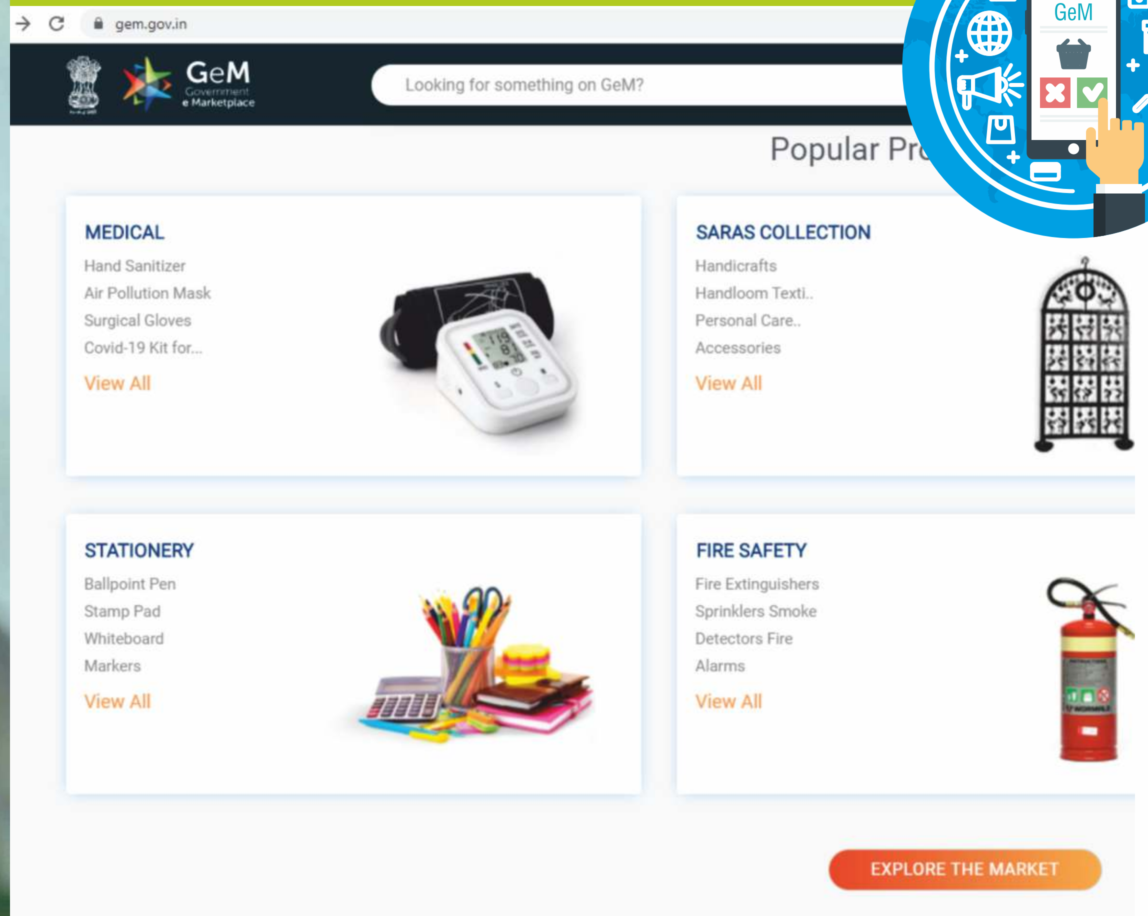

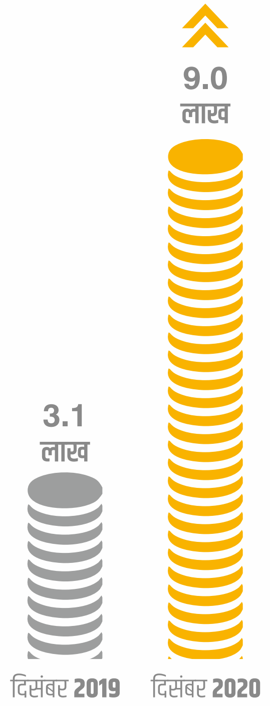

विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं में 190% वृद्धि

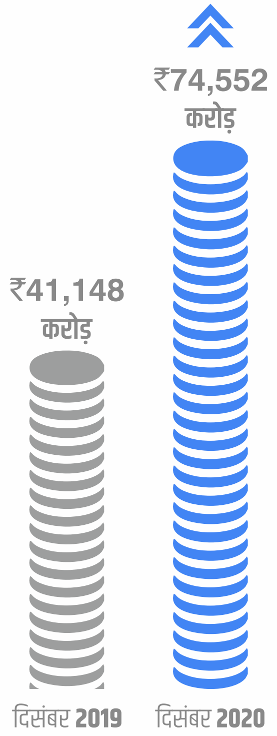

कारोबार मूल्य में 81% वृद्धि

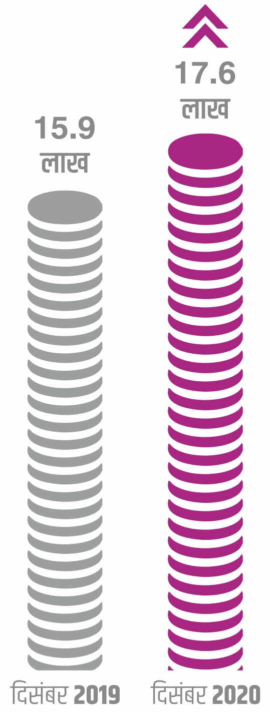

उत्पाद सूची में 11% वृद्धि

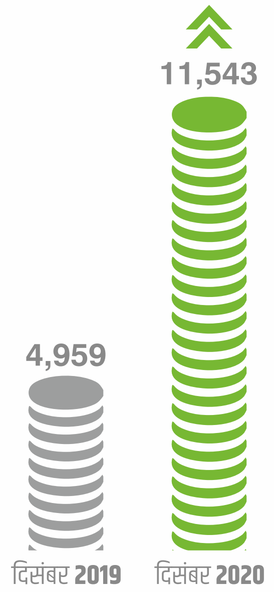

प्रस्तुत की गई श्रेणियों में 131% वृद्धि

नोट: 16 दिसंबर 2019 और 16 दिसंबर 2020 तक GeM पोर्टल की स्थिति

इनोवेट इन इंडिया

2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पेटेंट देने में **63 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है

छोटे व्यवसाय/एमएसएमई के लिए **पेटेंट आवेदन प्रोसेसिंग** शुल्क को कम किया

पेटेंट आवेदन की जांच की समय-सीमा को मई 2019 में **36-52 माह** से कम करके दिसंबर 2020 में 10-26 माह किया गया

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में 81 वें स्थान से छलांग लगा कर 2019 में **48 वें स्थान** पर पहुंच गया

26 नए भारतीय भौगोलिक संकेत (जीआई) जीआई रजिस्ट्री में पंजीकृत किए गए (1 मई 2019 से 24 दिसंबर 2020 तक)

स्टार्टअप इंडिया को दिए नए पंख

37,000 से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी गई। 50 प्रतिशत से अधिक को मई 2019 से मान्यता दी गई

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए

पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार - 35 श्रेणियों में 1,641 स्टार्टअप्स ने भाग लिया

4,905 पेटेंट आवेदनों को फाइलिंग शुल्क में 80 प्रतिशत और 12,264 ट्रेडमार्क आवेदनों पर 50 प्रतिशत की छूट

देश भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुधारने हेतु स्टार्टअप इकोसिस्टम को दिए गए प्रोत्साहन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया

स्टार्टअप को विकसित करने की सुविधा के लिए 39 विनियामक सुधार किए गए

आयकर अधिनियम की धारा 54 जीबी में संशोधन के तहत पूंजीगत लाभ पर कर में छूट का प्रावधान

धारा 80 आईएसी के तहत 3 वर्ष की आयकर अवकाश अवधि और आयकर अधिनियम की धारा 79 के तहत योग्य हानियां कैरी फारवर्ड करने की सुविधा

योग्य स्टार्टअप के लिए टर्नओवर मानदंड का विस्तार ₹100 करोड़ रुपये

अगस्त 2020 तक, 296 स्टार्टअप्स को आयकर अधिनियम के तहत छूट दी गई थी

ई-गवर्नेंस के साथ सुगम व्यापार

सभी **निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं** अर्थात् अग्रिम, ईपीसीजी, एमईआईएस ऑनलाइन संचालित

इस्पात आयात मॉनीटरिंग प्रणाली (एसआईएमएस) के लिए **ऑनलाइन अंतर-मंत्रालयी परामर्श** मॉड्यूल लागू

डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ़ ओरिजिन (सीओओ) जारी करने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (ईसीओओ)** आरंभ किया गया। **2 लाख से अधिक सीओओ जारी**

एल्युमीनियम, कॉपर, फुटवेयर, फर्नीचर, पेपर, खेल-कूद के सामान, जिम के उपकरण आदि के लिए आयात निगरानी प्रणाली (आईएमएस) विकसित की जा रही है

डिज़ाइन इन इंडिया के लिए अप-स्किलिंग

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019, संसद द्वारा पारित किया गया

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा में **4 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी)** को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का रूप प्रदत्त किया गया

डिजाइन संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण में **उत्कृष्टता को बढ़ावा**